बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं

- रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार का बजट 2024-25 - ₹ 76,000 करोड़
  - योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं का बजट - ₹ 39,000 करोड़
  - स्थापना बजट - ₹ 37,000 करोड़
  - राजस्व बजट - ₹ 60,910.75 करोड़
  - पूंजी बजट - ₹ 15,089.25 करोड़

- 2024-25 में बजट अनुमान 76,000 करोड़ रुपये है, जो कि 2023-24 के 74,900 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 1.47% अधिक है ।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 76,000 करोड़ रुपये का बजट मुख्य रूप से स्वयं के संसाधनों से वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रमुख घटको में स्वयं के कर राजस्व से 58,750 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व से 1000 करोड़ रुपये, लघु बचत ऋण से 10,000 करोड़ रुपये, 379 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियो से, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से 3223.94 करोड़ रुपये, भारत सरकार से अनुदान सहायता /सामान्य सहायता के रूप में 1168 करोड़ रुपये और शुरुआती शेष से 1478.95 करोड़ रुपये है।

दिल्ली का आर्थिक परिदृश्य

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 9.17% की दर से बढ़ा है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के 10.15 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष अनुमानित 11.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- दिल्ली की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का केवल 1.55% योगदान देती है। फिर भी, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान दोगुने से भी अधिक है। 2023-24 में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 3.89% होने जा रहा है।
- दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर 2014-15 में 2.47 लाख रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.62 लाख रुपये हो गई है; जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना अधिक है।

शिक्षा

- 2014-15 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ 24,000 कमरे ही उपलब्ध थे। पिछले 9 सालों में सरकार ने 22,711 नए क्लास रूम बनाए हैं ।
- विशिष्ट उत्कृष्टता स्कूलों (SoSEs) के तहत, दिल्ली में 56 डोमेन में 38 स्कूल परिसर स्थापित किए गए हैं, जिनमें एसटीईएम, मानविकी, प्रदर्शन और दृश्य कला और उच्च-स्तरीय 21 वीं सदी के कौशल शामिल हैं। 2024-25 बजट में SoSEs के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- 2015 से पहले दिल्ली सरकार के स्कूलों में 34,182 नियमित शिक्षक थे। अब, दिल्ली सरकार के स्कूलों में 47,914 नियमित शिक्षक हैं, और लगभग 7,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
- तकनीकी शिक्षा में सीटों की संख्या 2014-15 में 12,204 से बढ़कर 2023-24 में 62,000 हो गई है।
- विश्व स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना ; 2024-25 में एससीईआरटी को 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- नए स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मौजूदा कक्षाओं के रखरखाव के लिए 45 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है ।
- दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल (डीएमवीएस) के लिए एक नए स्टूडियो के निर्माण, बुनियादी ढांचे के निर्माण और शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए 12 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।
- बजट 2024-25 में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- 'मुख्यमंत्री सुपर टैलेंटेड कोचिंग योजना' सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को जेईई (मेन/एडवांस्ड) और एनईईटी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करती है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 600 छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- दिल्ली में एथलीटों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट 2024-25 में खेल शिक्षा के लिए 118 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 2024-25 में 16,396 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य

- दिल्ली सरकार के अंतर्गत 38 अस्पताल हैं जहां प्रतिदिन 81,000 से अधिक ओपीडी रोगियों और मासिक 65,806 आईपीडी रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है।
- 2014 में, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 9,523 बिस्तर थे, जबकि अब, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 13,708 बिस्तर हैं, जिससे सरकार 1.5 गुना अधिक रोगियों की देखभाल करने में सक्षम हो गई है।
- 2014 में सरकार के पास करीब 155 सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (CATS) एंबुलेंस थीं, जबकि आज दिल्ली में 380 CATS एंबुलेंस हैं । 2024-25 में, दिल्ली में CATS नई एंबुलेंस की खरीद के लिए 194 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लीनिक खोले गए, जहां हर दिन 64,000 लोगों को मुफ्त दवाएं, जांच और इलाज मिलता है। दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लीनिक के माध्यम से उत्कृष्ट चिकित्सा उपचार मिलता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए 2024-25 में 212 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार के अस्पताल विश्व स्तरीय बने रहें, जिसके लिए 6,215 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और सभी जरूरतमंद लोगों को समय पर मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 658 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों के रीमॉडलिंग के माध्यम से विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2024-25 में 8,685 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ-यात्रा

- मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत 2019 से अब तक 92 ट्रेनों के माध्यम से 87,000 बुजुर्ग और उनके परिवार तीर्थ यात्रा पर जा चुके हैं।

हमारे शहीदों का सम्मान

- पिछले 9 वर्षों में, सरकार ने 35 शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की है। सरकार कोविड फ्रंट-लाइन कार्यकर्ताओं के परिवारों का भी सम्मान करती है। महामारी के दौरान अपने जीवन का बलिदान देने वाले 92 COVID योद्धाओं के प्रत्येक परिवारों को 1 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री की सहायता और अनुग्रह राशि मिली है ।

सभी के लिए न्याय

- वित्तीय वर्ष 2014-15 में न्याय व्यवस्था का बजट 760 करोड़ रुपये और 2024-25 में ये करीब 4 गुना बढ़कर 3,098 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है ।
- 2024-25 में सरकार रोहिणी, कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और राउज एवेन्यू में चार अत्याधुनिक कोर्ट परिसरों का निर्माण शुरू करने जा रही है।
- जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए एक नई योजना प्रस्तावित है और 2024-25 के बजट अनुमान में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- डीएसएलएसए के माध्यम से मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 2016 में केवल 33,000 थी, जबकि पिछले साल यह संख्या लगभग चार गुना बढ़कर 1,25,000 तक पहुंच गई।

रोज़गार

- बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में लगभग 2,40,000 छात्रों ने 38,000 टीमें बनाईं और अपने बिजनेस आइडिया पर काम किया। 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं ।
- दिल्ली सरकार के स्कूलों में शुरू की गई उद्यमिता क्रांति से प्रेरणा लेते हुए, 2024-25 से सभी विश्वविद्यालयों में 'बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर' लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत सरकार 2024-25 के दौरान दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों के स्टार्ट-अप में 15 करोड़ रुपये निवेश करेगी।

दिल्ली के हर घर को रोशन करना / ऊर्जा

- 2023-24 में, दिल्ली ने बिना किसी लोड शेडिंग के 7,438 मेगावाट की अपनी चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया।
- 22 लाख से अधिक परिवारों को शून्य बिजली बिल मिलता है और 40.22 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार से बिजली सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।
- दिल्ली की लगभग 30% बिजली आपूर्ति हरित और नवीकरणीय ऊर्जा से आती है।
- दिल्ली में 1280 सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगे हुए हैं और 2024-25 तक दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली हर इमारत की छत पर सोलर प्लांट होंगे। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2027 तक हरित ऊर्जा से आने वाली 4500 मेगावाट या कुल बिजली आपूर्ति का 25% का लक्ष्य रखते हुए, दिल्ली सरकार से संबंधित प्रत्येक इमारत की छत पर सौर संयंत्र लगाना है।
- पावर सेक्टर के लिए 2024-25 में 3,353 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

पानी

- दिल्ली में लगभग 62.5% घरों, यानी लगभग 17 लाख परिवारों को पानी पूरी तरह से मुफ्त मिलता है।
- दिल्ली में पानी की उपलब्धता 840 एमजीडी से बढ़कर 1009 एमजीडी हो गई है।
- 99.6% अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइनें हैं।
- 2014 के बाद, सरकार ने 2422 किलोमीटर नई पानी पाइपलाइन और 3100 किलोमीटर नई सीवर पाइपलाइन बिछाई है।
- दिल्ली में हर घर के लिए पानी और सीवरेज सुविधाओं का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

शहरी बुनियादी ढांचा

- दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों को जोड़ने वाली आंतरिक सड़कों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। 'मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना' के तहत अब तक लगभग 850 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है और दिल्ली की सड़कों और गलियों की स्थिति में लगातार सुधार किया जा रहा है और डार्क स्पॉट को कम करके सड़कों को सुरक्षित बनाया गया है। इस योजना के लिए 2024-25 में 275 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।
- 'बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन' योजना के तहत, जिसे MLALAD योजना के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2023-24 के लिए 1,002 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 717 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस विकास कार्य को जारी रखने के लिए, बजट अनुमान 2024-25 में MLALAD योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र की योजनाओं के लिए 9,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- अनधिकृत कॉलोनियां - सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में नालियां और पानी की लाइनें बढ़ाने के साथ-साथ ऐसी 1355 कॉलोनियों में 5175 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में अनाधिकृत कॉलोनियों के उत्थान के लिए बजट में 902 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़क अवसंरचना

- अब दिल्ली में 2.60 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं।
- सरकार ने शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए पिछले 9 वर्षों के दौरान 30 नए गलियारे, फ्लाईओवर, पुल और अंडरपास का निर्माण किया है। इनमें से कुछ में रिंग रोड पर भलस्वा, बुराड़ी, मुकुंदपुर और जगतपुर फ्लाईओवर, मधुबन चौक और मुकरबा चौक के बीच एक ऊंचा गलियारा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज, शास्त्री पार्क-सीलमपुर फ्लाईओवर, आश्रम चौक अंडरपास और दक्षिण दिल्ली में फ्लाईओवर शामिल हैं। सराय काले खां फ्लाईओवर, आउटर रिंग रोड पर आरटीआर फ्लाईओवर, बेनिटो जुआरेज़ अंडरपास, और बहुत कुछ।
- 2024-25 में कई नए फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर का काम पूरा करके दिल्ली की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा- बारापुला चरण-III; करावल नगर, गोंडा होते हुए बृजपुरी जंक्शन पर डबल डेकर मेट्रो फ्लाईओवर; नंद नगरी से गगन सिनेमा जंक्शन तक फ्लाईओवर; रानी झाँसी रोड जंक्शन से आज़ादपुर कॉरिडोर पर डबल डेकर मेट्रो फ्लाईओवर; आनंद विहार आरओबी से अप्सरा बॉर्डर आरओबी तक फ्लाईओवर और आउटर रिंग रोड मुकरबा चौक पर अंडरपास।
- बजट 2024-25 में दिल्ली में सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए 1,768 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

परिवहन

- लगभग 11 लाख महिलाएं हर दिन डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा करती हैं।
- पिछले 9 वर्षों में, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की लंबाई दोगुनी होकर 393 किलोमीटर तक पहुंच गई है, और स्टेशनों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है।
- 1650 ई-बसों के बेड़े के साथ, दिल्ली अब दुनिया के शहरों में तीसरे स्थान पर है। आज, दिल्ली के पास 7582 बसों का एक उल्लेखनीय बेड़ा है, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिक है।
- सरकार 2080 नौ-मीटर ई-बसें खरीदेगी, जिनका उपयोग अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिए मोहल्ला बसों के रूप में किया जाएगा।
- 2025 तक दिल्ली में 10,000 से ज्यादा बसें होंगी, जिनमें से 80% इलेक्ट्रिक बसें होंगी।

- दिल्ली में वर्तमान में 7582 बसों का बस बेड़ा है, जिसका उपयोग दैनिक आधार पर 41 लाख से अधिक यात्री कर रहे हैं। इस बेड़े को और अधिक विस्तारित करने के लिए, 1,900 नई ई-बसों की नियुक्ति के लिए एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- बजट 2024-25 के दौरान, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 510 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में 'पिंक टिकट' के जरिए महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना को जारी रखने के लिए 2024-25 में 340 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव है।
- दिल्ली मेट्रो के चरण-4 के कार्य के तहत तीन कॉरिडोर, जनकपुरी पश्चिम से रामकृष्ण आश्रम कॉरिडोर, दिल्ली एयरोसिटी से तुगलकाबाद स्टेशन कॉरिडोर, मजलिस पार्क से मौजपुर कॉरिडोर के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कुल 65.20 किलोमीटर लंबे इन तीन मेट्रो कॉरिडोर पर 45 स्टेशन होंगे। 2024-25 में, दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।
- दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बजट परिव्ययवित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5702 करोड़ का प्रस्ताव है।

दिल्ली के गांवों का विकास

- गांवों में बेहतर सड़क ढांचा विकसित करने के लिए सरकार 2024-25 में दिल्ली के 360 से ज्यादा गांवों में करीब 1000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाएगी। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के गांवों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- लगभग 9.03 लाख लाभार्थी हर महीने 2,000 से 2,500 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहे हैं । इसमें 4 लाख वरिष्ठ नागरिक, 3.75 लाख संकटग्रस्त महिलाएं और 1.23 लाख विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति शामिल हैं। 2024-25 के बजट में इन लाभार्थियों के लिए 2,714 करोड़ रुपये प्रस्तावित है ।
- 2014 में, दिल्ली में लगभग 2 लाख बच्चे गंभीर और मध्यम कुपोषण से प्रभावित थे, और आज, यह संख्या 91.5% तक कम हो गई है, केवल 16,814 कुपोषित बच्चे हैं।
- महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2024-25 से एक नई योजना "मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना" प्रस्तावित है। इस योजना के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला 1000 रुपये प्रति माह राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, उन महिलाओं को छोड़कर जो वर्तमान में किसी भी सरकारी पेंशन योजना का हिस्सा हैं, सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
- समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 6,216 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

- दिल्ली सरकार बजट वर्ष 2024-25 में स्थानीय निकाय को कुल 8,423 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी । इसमें से 3,153 करोड़ रुपये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के लिए होंगे। 2,955 करोड़ रुपये बेसिक टैक्स असाइनमेंट (बीटीए) के रूप में दिए जाएंगे और स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क तथा एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में 2,315 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

********** **